RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 268
दि. 30.01.2026, शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रधानमंत्री ने एआई सेक्टर में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने एआई तकनीक में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत को वैश्विक मंच पर एआई में अग्रणी बनाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की

पीएम ने एक ऐसे एआई इकोसिस्टम की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया जो पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित हो

पीएम ने कहा कि एआई के नैतिक उपयोग पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए

यूपीआई के माध्यम से भारत ने अपनी तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया है और एआई के क्षेत्र में भी इसी सफलता को दोहराया जा सकता है : पीएम

हमें अपनी तकनीक से न केवल प्रभाव पैदा करना है, बल्कि दुनिया को प्रेरित भी करना है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक के उपयोग का आह्वान किया

((जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने आवास, लोक कल्याण मार्ग पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की।

फरवरी में होने वाले आगामी इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट के अनुरूप, इस बातचीत का उद्देश्य स्ट्रेटेजिक सहयोग को बढ़ावा देना, एआई नवाचारों का प्रदर्शन करना और भारत के एआई मिशन के लक्ष्यों को गति देना था। बातचीत के दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने एआई तकनीक में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य के प्रति अपना मजबूत समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने भारत को ग्लोबल लेवल पर एआई क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और संसाधनों की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को अपनाने और राष्ट्रीय

विकास में इसके योगदान पर जोर दिया। उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक के उपयोग का भी आह्वान किया।

आगामी एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सभी व्यक्तियों और कंपनियों को नए अवसरों को तलाशने और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए इस शिखर सम्मेलन का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से भारत ने अपनी तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया है और एआई के क्षेत्र में भी इसी सफलता को दोहराया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भारत के पास पैमाना, विविधता और लोकतंत्र का अनूठा कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण दुनिया भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे पर भरोसा करती है। 'एआई फॉर ऑल' के अपने विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी से प्रभाव पैदा करने के साथ-साथ दुनिया को प्रेरित करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से भारत को सभी वैश्विक एआई प्रयासों के लिए एक बेहतरीन गंतव्य बनाने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने डेटा सुरक्षा और तकनीक को सबके लिए सुलभ बनाने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे एआई इकोसिस्टम की दिशा में काम करना चाहिए जो पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित हो। उन्होंने यह भी कहा कि एआई के नैतिक उपयोग पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, साथ ही एआई कौशल और प्रतिभा निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपील की कि भारत का एआई इकोसिस्टम राष्ट्र के चरित्र और मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

इस हाई-लेवल राउंडटेबल बैठक में विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, जोहो कॉर्पोरेशन, एलटीआई माइंडट्री, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, अडानीकनेक्स, नेक्स्ट्रा डेटा और नेटवेब टेक्नोलॉजीज जैसी एआई क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ-साथ आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस बातचीत में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद भी शामिल हुए।

4 दिनों तक चली सेरेमनी-3 सेनाओं का राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट

((जीएनएस)।

विजय चौक की रंग-बिरंगी लाइटिंग, तीनों सेनाओं के बैंड्स की मधुर धुनें और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ढशीशील्लइ उऋ४र्स्र ट४१४) की मौजूदगी में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समापन हुआ। शाम को आयोजित बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी ने 4 दिनों तक चले गणतंत्र दिवस आयोजनों का शानदार अंत किया। इस दौरान भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड्स ने मिलकर देशभर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उनके साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए।

बीटिंग द रिट्रीट एक 300 साल पुरानी सैन्य परंपरा है। राजा-महाराजाओं के समय में सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद होने का ऐलान होता था। बिगुल बजते ही सैनिक हथियार नीचे रखकर बैरक लौटते थे। आज यह सेना की 'बैरक वापसी' का प्रतीक है। भारत में यह परंपरा 1950 के दशक से चली आ रही है। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका समेत कई देशों में भी यह आयोजन होता है।

इस साल की सेरेमनी में क्या खास था?

सीटिंग एनक्लोजर के नामः पहली बार विजय चौक की सीटिंग जगहों को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए -बांसुरी, डमरू, एकतारा, तबला, वीणा, सितार, शहनाई, संतूर, सरोद, पखावज, नगाड़ा, मृदंगम। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की पहल थी।

लाइटिंग और सजावटः विजय चौक की सभी प्रमुख इमारतें रंग-बिरंगी लाइटिंग से जगमगाईं।

मास बैंड का कमालः तीनों सेनाओं और उअढक्र के बैंड्स ने मिलकर धुनें बजाईं -'भारत की शान', 'वंदे मातरम्', 'ड्रमर्स कॉल'। समापन 'सारे जहां से अच्छा' के साथ हुआ।

सेरेमनी का क्रम क्या था? कौन-कौन सी धुनें बजीं?

शुरूआत में सेना ने राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया। तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' बजा। तीनों सेनाओं के बैंड ने 'कदम-कदम बढ़ाए जा' से शुरूआत की।

पाइप्स एंड ड्रम्स बैंडः 'अतुल्य भारत', 'वीर सैनिक', 'मिली झुली', 'नृत्य सरिता', 'मरूनी', 'झेलम'।

उअढक्रबैंड्सः 'विजय भारत', 'हथरोही', 'जय हो', 'वीर सिपाही'।

वायुसेना बैंडः 'ब्रेव वॉरियर', 'ट्वाइलाइट', 'अलर्ट', 'फ्लाइंग स्टार'।

नौसेना बैंडः 'नमस्ते', 'सागर पवन', 'मातृभूमि', 'तेजस्वी', 'जय भारती'।

सेना बैंडः 'विजयी भारत', 'आरंभ है प्रचंड है', 'ऐ वतन, ऐ वतन', 'आनंद मठ', 'सुगम्य भारत', 'सितारे हिंद'।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, इन 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हो गई है. बैठक में सरकार ने 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और शहरी विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

((जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इन प्रस्तावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और शहरी विकास से जुड़े अहम फैसले शामिल रहे. आइए एक नजर डालते हैं किन 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

कैबिनेट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों और परिषद से मान्यता प्राप्त अनुदानित और

स्ववित्तपोषित स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (उहरठ), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षक-शिक्षिकाओं और प्रधानमंत्री पोषण योजना की रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस सुविधा का लाभ इन सभी कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्य भी उठा सकेंगे.

माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज

इसके साथ ही प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी.

कैबिनेट बैठक में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. यह मामला मेरठ जिले की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गोसाई से जुड़ा है।

प्रधानमंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण को भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस की एक व्यापक तस्वीर के रूप में रेखांकित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस (सुधारों की गति) की एक व्यापक तस्वीर पेश करता है, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बावजूद हमारी निरंतर प्रगति को दशार्ता है।

श्री मोदी ने रेखांकित किया कि आर्थिक सर्वेक्षण मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे, निरंतर विकास की गति और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की विस्तार लेती भूमिका को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "यह सर्वेक्षण समावेशी विकास के महत्व पर जोर देता है, जिसमें किसानों, एमएसएमई, युवाओं के लिए रोजगार और समाज कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8.4 अरब डॉलर, निजी क्षेत्र के लिए खुलने के बाद लगभग 400 स्टार्ट-अप सक्रियः डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब लगभग 8.4 अरब

डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसमें 399 स्टार्ट-अप लॉन्च वाहन, उपग्रह, प्रणोदन प्रणाली और अंतरिक्ष-ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

डॉ. सिंह ने बताया कि यह विस्तार 2019 के बाद लिए गई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के कारण हुआ, जिनमें अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना शामिल है।

लंदन में बंगला- दुबई में प्रॉपर्टी, खामेनेई के पास विदेशों में अकूत संपत्ति देख भड़के ईरान

((जीएनएस)।

उत्तरी लंदन की एक पेड़-लाइन वाली सड़क है, जिसे "बिलियनेयर रो" कहा जाता है, वहां कई आलीशान हवेलियां ऊंची झाड़ियों और काले दरवाजों के पीछे छिपी हुई हैं। इन घरों के बाहर रोज स्कूल के बच्चे आते-जाते दिखते हैं, वहीं काली रवश में निजी सुरक्षा गार्ड लगातार गश्त करते रहते हैं। बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन इन लक्जरी घरों के पीछे एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क छुपा है, जिसके तार तेहरान से दुबई और फ्रैंकफर्ट तक जुड़े हुए हैं।

ब्लूमबर्ग की जांचः असली मालिक कौन?

ब्लूमबर्ग द्वारा देखे गए दस्तावेजों और जानकारियों के मुताबिक, इन संपत्तियों का असली स्वामित्व कई

शेल कंपनियों के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोजतबा खामेनेई से जुड़ा हुआ है।

56 साल के मौलवी मोजतबा खामेनेई को उनके पिता का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, वह एक बड़े और जटिल निवेश साम्राज्य की देखरेख करते हैं, हालांकि वह सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं।

सीधे नाम पर कुछ नहीं, लेकिन कंट्रोल पूरा

सूत्रों के अनुसार, मोजतबा खामेनेई अपनी संपत्ति सीधे अपने नाम पर नहीं रखते। लेकिन 2011 से जुड़े कई बड़े सौदों में उनकी सीधी भूमिका रही है। उनकी वित्तीय ताकत फारसी खाड़ी में शिपिंग, स्विस बैंक खातों और ब्रिटेन में 100 मिलियन पाउंड (करीब 1300 करोड़ भारतीय रुपए) से ज्यादा की लक्जरी संपत्तियों तक फैली हुई है।

अंबेडकर प्रतिमा विवादः शिवाजी चौराहा यात्रा रोके जाने पर तनाव, दामोदर यादव का सरकार पर बड़ा आरोप

((जीएनएस)।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक बड़ा सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निमार्ता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प और मजबूत हुआ।

आजाद समाज पार्टी (भीम आर्मी) के मंडल पदाधिकारी दामोदर यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "हम हर हाल में बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में स्थापित करेंगे। यह हमारा अटल और अटूट संकल्प है। किसी भी दबाव में हम पीछे नहीं हटेंगे।"

यह विवाद मई 2025 से चला आ रहा है, जब ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ परिसर में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने की मांग पर वकीलों के दो गुटों में टकराव हुआ था। एक पक्ष इसे संविधान के सम्मान से जोड़ता है, जबकि दूसरे पक्ष ने परिसर की 'पवित्रता' और 'परंपरा' का हवाला देकर विरोध किया। तब से यह मुद्दा सड़कों, अदालतों और राजनीति तक पहुंच गया है।

भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता, बाबा साहब के अनुयायी, दलित-बहुजन संगठन के पदाधिकारी और आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मनुवादी सोच के खिलाफ एकजुटता दिखाना और ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा स्थापना की मांग को तेज करना था।

कार्यक्रम के दौरान दामोदर यादव ने

बताया कि मोहन यादव सरकार द्वारा पहले से तय कार्यक्रम के तहत बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिवाजी चौराहा तक शांतिपूर्ण यात्रा निकालने की योजना थी। हजारों लोग जुटे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यात्रा को शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक पहुंचने से रोक दिया। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और जमकर हंगामा हुआ।

दामोदर यादव ने पुलिस और प्रशासन के साथ तीखी बहस की। उन्होंने कड़ा आरोप लगाते हुए कहा, "यह सिर्फ बाबा साहब का नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अपमान है। सरकार जानबूझकर जनभावनाओं को कुचलने का प्रयास कर रही है। शिवाजी चौराहा तक जाने से रोकना संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है।"

संकल्प और आगे की रणनीति

दामोदर यादव ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "हम किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। यदि सरकार नहीं मानती, तो हम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। दीक्षा भूमि नागपुर से लेकर भोपाल तक का यह संकल्प अब अटूट हो चुका है।"

उन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए, क्योंकि वे संविधान के निमार्ता हैं और न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं। "अगर अन्य राज्यों में अंबेडकर जी की प्रतिमा न्यायालयों में है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं?" उन्होंने सवाल उठाया।

विवाद की पृष्ठभूमि

मई 2025ः ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा लगाने की मांग पर वकीलों में टकराव, पुलिस हस्तक्षेप।

अक्टूबर 2025ः वकील अनिल मिश्रा की कथित टिप्पणी पर तनाव, सोशल मीडिया पोस्ट हटाए गए, ग्वालियर में प्रतिबंधात्मक आदेश।

जनवरी 2026ः दामोदर यादव ने कई बार चेतावनी दी, 14 मार्च तक समयसीमा तय की।

वर्तमानः भोपाल कार्यक्रम में यात्रा रोके जाने से नया विवाद, पुलिस-कार्यकताओं में बहस।

सीएम मोहन यादव सरकार ने पहले कहा था कि चीफ जस्टिस द्वारा गठित कमेटी का फैसला अंतिम होगा और सरकार उसका समर्थन करेगी। लेकिन कार्यकताओं का आरोप है कि सरकार देरी कर रही है और जनभावनाओं की अनदेखी कर रही है।

सामाजिक संगठनों का समर्थन

कार्यक्रम में विभिन्न दलित-बहुजन संगठनों, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य सामाजिक कार्यकताओं ने एकजुटता जताई। कई वक्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ प्रतिमा का मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान के सम्मान और सामाजिक न्याय का सवाल है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन और पूजा-अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण कल्याण की प्रार्थना की

गांधीनगर, 29 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के चरणों में शीश नवाकर दर्शन किए और धन्यता महसूस की।

मुख्यमंत्री ने भगवान द्वारकाधीश के श्री चरणों में राज्य के नागरिकों की सुख-शांति और समृद्धि की हृदयपूर्वक प्रार्थना की। उन्होंने भक्तिभाव से शास्त्रोक्त विधिपूर्वक पादुका पूजन भी किया।

मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में उपस्थित दर्शनार्थियों का अभिवान स्वीकार किया और सभी को 'जय द्वारकाधीश' कहा।

जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र, द्वारका मंदिर की प्रतिकृति, फुल और तुलसी से बनी अनुग्रहम अगरबत्ती तथा प्रसाद अर्पित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मंत्री और विधायक श्री मुळुभाई बेरा, जिला कलेक्टर श्री राजेश तन्ना, पुलिस अधीक्षक श्री जयराजसिंह वाळा और अग्रणी श्री मयूरभाई गढ़वी सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

सम्पादकीय

विमान दुर्घटनाओं के बाद जैसी जांच और सुधार की जरूरत है वह नहीं हो पाती

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक विमान दुर्घटना के शिकार हो गए। इसके पहले विजय रूपाणी भी विमान दुर्घटना के शिकार हुए थे। दो दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है किन्तु लोग माधवराव सिंधिया के विमान दुर्घटना को भूल नहीं पाए हैं। जनरल विपिन रावत के हेलीकाप्टर दुर्घटना से भारत की दुनियाभर में जगहंसाई हो चुकी है। इसलिए विमान दुर्घटनाओं के बाद जैसी जांच और सुधार की जरूरत है वह नहीं हो पाती। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का वह स्वायत्त शासी संस्था जिस पर विमानों के परिचालन का दायित्व है, उसकी कार्य पद्धति में सुधार निराशाजनक ही रह जाती है। यही कारण है कि इस विमान दुर्घटना में भी तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। यदि सरकार विमान दुर्घटनाओं के बाद रिपोर्ट जारी करती और सुझाए गए तरीकों को अपनाती तो विमान दुर्घटनाएं भी कम होती और साथ ही सरकार एवं संस्थाओं के प्राति आशंका की संभावनाएं भी न रहतीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्थापित परम्पराओं के प्राति उदासीनता भी इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक नियम है कि कोई विमान उड़ान भरने के पहले इंजीनियर की जांच प्राव्रिया से गुजरता है और जब इंजीनियर विमान के पूरी तरह उड़ने के योग्य होने की पुष्टि करता है तभी पायलट उस विमान को उड़ाते हैं। लेकिन देखा जाता है कि विमान वंपनियां जांच प्राव्रिया से बचती हैं और कभी-कभी तो समयाभाव में राजनेता भी जल्दबाजी के कारण इंजीनियर द्वारा जांच कराने की देरी से बचना चाहते हैं। वुल मिलाकर स्थिति यह है कि अजित पवार जिला परिषद चुनाव प्राचार के लिए जा रहे थे और बारामती हवाई अड्डे के पास यह हादसा हो गया। ऐसी विमान दुर्घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, इसलिए इस विमान दुर्घटना पर भी वुछ लोगों को सवाल उठाने का अवसर मिला किन्तु यह अवसर भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अफसरशाही और डीजीसीए के नकारापन के कारण ही उन्हें मिला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अजित परार के जाने के बाद अब उनके परिवार, पाटा और सरकार का क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। 6 फरवरी 2024 को ही चुनाव आयोग ने अजित पवार के पक्ष में अपना अंतिम पैसला सुना दिया था। किन्तु स्थानीय चुनावों में जिस तरह अजित पवार और शरद पवार के नेतृत्व वाली दोनों एनसीपी ने चुनाव लड़ा, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि दोनों परिवारों में पाटा के भविष्य को लेकर एक सहमति बनती जरूर दिख रही थी। आज भले ही अजित पवार की पत्नी राज्यसभा की सदस्य हैं किन्तु पाटा चलाने में वह उतनी सक्षम नहीं हैं जितना कि खुद शरद पवार या उनकी पुत्री सुप्रिया सुले हैं। समस्या सबसे बड़ी यह है कि एनसीपी जिसका नेतृत्व अजित पवार कर रहे थे उसके पास 40 विधायक, दो वैबिनेट मंत्री एक लोकसभा सांसद और दो राज्य सभा सदस्य हैं। उनकी पाटा की महत्वाकांक्षा शासन से दूर नहीं हो सकती। इसलिए लगता नहीं कि अजित पवार की एनसीपी राज्य की एनडीए सरकार से अलग होगी। चूंकि शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों ही एनडीए के प्राति पहले जैसे कटु विरोधी रवैया नहीं अपना रहे हैं, इसलिए लगता नहीं कि अजित पवार के जाने के बाद उनकी पाटा देवेन्द्र फडणवीस सरकार से अलग हो जाएगी। लेकिन यह भी सही है कि मुस्लिम आधार होने के कारण एनसीपी भाजपा से अलग अस्तित्व बनाकर रखना भी चाहेगी। बहरहाल राजनीति, पारिवारिक भावना और मौजूदा परिस्थिति के परिप्रोक्ष्य में अजित पवार के जाने के बाद उस एनसीपी का क्या होगा जिसका वह नेतृत्व कर रहे थे, इसका पैसला तो राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व परिवार कर ही लेगा किन्तु विमान हादसों, सरकार एवं डीजीसीए की कायंर्वुशलता पर जो बड़ा सवाल उठ रहा है, उसका जवाब पूरे देश को चाहिए।

गुजरात की झाँकी ने लगातार चौथे वर्ष 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर रचा इतिहास

लगातार तीन वर्ष 2023, 2024 और 2025 में भी गुजरात की झाँकी ने इसी श्रेणी में हासिल किया था प्रथम पुरस्कार

गांधीनगर, 29 जनवरीः 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्यपथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में गुजरात के 'स्वतंत्रता का मंत्रः वंदेमातरम्' थीम आधारित झाँकी ने दर्शकों के बीच विशेष आकर्षण और उत्सुकता पैदा की। गुजरात की इस झाँकी ने गणतंत्र दिवस परेड में 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गए गुजरात की झाँकी की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र भक्ति के साथ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को प्रभावी रूप से उजागर करने के कारण गुजरात की झाँकी को जनता का व्यापक समर्थन और सराहना मिली है।

केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा MyGov पोर्टल पर 26 जनवरी से 27 जनवरी रात 11:45 बजे तक आयोजित ऑनलाइन मतदान में गुजरात की झाँकी पहले घंटे से लेकर दूसरे दिन के अंत तक लगातार अग्रणी रहा और कुल मतों के 43 प्रतिशत वोट प्राप्त कर पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर विजयी रहा। दूसरे स्थान पर रहे उत्तर प्रदेश को 9 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, जबकि शेष 15 राज्यों को क्रमशः कम प्रतिशत में मत मिले।

इस वर्ष कर्तव्यपथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में गुजरात राज्य के सूचना विभाग द्वारा प्रस्तुत झाँकी में 'वंदे मातरम्' और स्वदेशी आंदोलन के समन्वय से उत्पन्न स्वतंत्रता की क्रांति से लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी मंत्र की यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया।

उल्लेखनीय है कि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी अवॉर्ड में गुजरात की झाँकी की अग्रणी परंपरा की शुरूआत वर्ष 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस की

राष्ट्रीय परेड से हुई थी। उस वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 'क्लीन ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात' की झाँकी में प्रधानमंत्री के नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के आह्वान को साकार करने में गुजरात की पहल को दशार्या गया था।

इसके बाद वर्ष 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में गुजरात द्वारा प्रस्तुत 'धोरडो झ वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज (वठहळड)' थीम आधारित झाँकी को भी 'पॉपुलर चॉइस' कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, झाँकी की श्रेष्ठता के लिए चयन समिति यानी ज्यूरी चॉइस में भी गुजरात की झाँकी ने वर्ष 2024 में द्वितीय स्थान हासिल किया था।

वहीं वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में गुजरात द्वारा आधुनिक विकास की जिस तेज रफ्तार यात्रा को दशार्या गया, उसे प्राचीन विरासत के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत 'आनर्तपुर से एकतानगर तक- विरासत से विकास का अद्भुत संगम' झाँकी को भी 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' प्राप्त हुआ।

इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026 में 'स्वतंत्रता का मंत्रः वंदेमातरम्' थीम आधारित गुजरात की झाँकी को भी 'पॉपुलर चॉइस अवॉर्ड' मिलने से राज्य की उपलब्धियों में एक और गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया है।

उल्लेखनीय है कि आगामी 30 जनवरी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री की उपस्थिति में गुजरात को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी सूरत का स्मार्ट मॉडल : 'डायमंड सिटी' अब बनेगी 'जीरो वेस्ट सिटी'

कूड़ा प्रबंधन में देश की 'रोल मॉडल' डायमंड सिटी अब 'सर्कुलर इकोनॉमी' की ओर अग्रसर

निर्माण कार्य के कूड़े की 100 प्रतिशत रीसाइक्लिंग : हर वर्ष लगभग 500 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाती है, जो 2,50,000 किलो कोयले की बचत समान है

सूरत महानगर पालिका ने सर्वप्रथम क्लीन कन्स्ट्रक्शन गाइडलाइन लागू की

टिकाऊ शहरी विकास तथा कन्स्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन (सी एण्ड डी) वेस्ट का स्मार्ट मैनेजमेंट कर रही सूरत महानगर पालिका

क्लीन सिटी सूरत में डिमोलिशन वेस्ट अब संपदा बन रहा है

गांधीनगर, 29 जनवरी : एक समय केवल हीरा एवं कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात सूरत शहर आज पर्यावरण संरक्षण तथा कूड़ा निकासी के लिए समग्र देश में पथदर्शक बन रहा है। सूरत अब केवल 'डायमंड सिटी' के रूप में नहीं, बल्कि 'जीरो वेस्ट सिटी' की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए 'अर्बन डेवलपमेंट इयर झ शहरी विकास वर्ष' के अवसर पर सूरत महानगर पालिका ने आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ 'ग्रीन ग्रोथ' को भी प्राथमिकता दी है।

विकास की बड़ी छलांग लगा रहा सूरत शहर अब पर्यावरण संरक्षण में भी देश का नेतृत्व कर रहा है। महानगर पालिका ने आगामी दो वर्ष में शहर में निकलने वाले ठोस निर्माण कार्य कूड़े (सी एण्ड डी वेस्ट) की 100 प्रतिशत रीसाइक्लिंग का लक्ष्य रखा है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि शहर का कोई भी कन्स्ट्रक्शन वेस्ट डंपिंग साइट तक पहुँचने की बजाय निर्माण स्थल पर ही या प्लांट में ही रिसाइकल होकर पुनरुपयोग में लिया जाए।

सूरत महानगर पालिका द्वारा शहर के कन्स्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का वैज्ञानिक ढंग से एकत्रीकरण कर उसे पुनः उपयोग में लेने के लिए कार्यरत सी एण्ड डी वेस्ट रीसाइक्लिंग प्लांट अब समग्र भारत के लिए एक उदाहरणीय मॉडल बना है। यह प्रोजेक्ट शहर की साफ-सफाई के साथ पर्यावरण की रक्षा करने तथा प्राकृतिक संसाधन बचाने में भी योगदान दे रहा है।

निर्माण कार्य के कूड़े की 100

प्रतिशत रीसाइक्लिंग करने वाले सूरत की यह स्मार्ट पहल केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण जतन का बड़ा अभियान बनी है। इस रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हर वर्ष 500 प्रतिशत से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटता है, जो 2,50,000 किलो कोयले की बचत समान है। इससे पत्थर तथा रेत जैसे प्राकृतिक संसाधनों के खनन पर बोझ कम हुआ है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में समग्र भारत में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सूरत ने देश में फिर एक बार स्वच्छता में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। सुपर स्वच्छ लीग में सूरत निरंतर अग्रसर रहा है तथा जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की ओर दृढ़ प्रयास हो रहे हैं। सूरत मनपा, राज्य एवं केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में कूड़े की वैज्ञानिक ढंग से रीसाइक्लिंग तथा वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। शहर में कन्स्ट्रक्शन तथा डिमोलिशन वेस्ट के ठोस कूड़े से बेस्ट प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए सी एण्ड डी प्लांट की स्थापना की गई है।

सूरत के कोसाड में 300 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अंतर्गत कार्यरत है, जिसमें दैनिक अनुमानित 80 मैट्रिक टन डिमोलिशन वेस्ट रीसाइकिल होता है। इस प्रकार; सी एण्ड डी वेस्ट से पेवर ब्लॉक्स तथा विभिन्न प्रकार के कन्स्ट्रक्शन वेस्ट मटीरियल्स से उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जाते हैं।

क्लीन सिटी सूरत में डिमोलिशन वेस्ट अब वेस्ट नहीं, बल्कि वेल्थ बन रहा है। सूरत मनपा द्वारा क्लीन कन्स्ट्रक्शन गाइडलाइन लागू की गई है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही कन्स्ट्रक्शन वेस्ट उठवाने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। सूरत मनपा द्वारा एक प्रेरणादायी निर्णय लिए जाने से प्लांट में निकलने वाली रिसाइकिल सामग्री को सरकारी टेंडरों में भी 20 प्रतिशत तक रिसाइकिल सामग्री का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इस नीति से रिसाइकिल हुई वस्तुओं के बाजार को गति मिलेगी और 'सर्कुलर इकोनॉमी' मजबूत बनेगी।

सूरत मनपा द्वारा लागू क्लीन कन्स्ट्रक्शन गाइडलाइन शहर के वायु प्रदूषण को घटाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। स्मार्ट मॉनिटरिंग के कारण नागरिकों की शिकायतों में कमी आई है और सी एण्ड डी की 100 प्रतिशत रीसाइक्लिंग की जाती है। कन्स्ट्रक्शन साइट्स पर पतरे, शेड्स, धूल नियंत्रण के लिए स्प्रिंकलर्स तथा ग्रीन नेट का अनिवार्य उपयोग; ये सब मिलकर सूरत को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुवासित बनाते हैं।

कोसाड स्थित प्लांट में ईंट, कंक्रीट, लोहे के टुकड़े एकत्र कर साइंटिफिक प्रोसेसिंग के जरिये पुनः उपयोग

कोसाड स्थित प्लांट वर्ष 2018 से कार्यरत हुआ। तब से सूरत मनपा द्वारा कलेक्शन सिस्टम मजबूत बनाए जाने से सी एण्ड डी ठोस कूड़े का कलेक्शन क्रमशः बढ़ा है, जिसमें वर्ष 2018-19 में 65,746 मैट्रिक टन, 2019-20 में 37,457 मैट्रिक टन, 2020-21 में 10,614 मैट्रिक टन, 2021-22 में 23,315 मैट्रिक टन, 2022-23 में 41,451 मैट्रिक टन, 2023-24 में 49,381 मैट्रिक टन तथा 2024-25 में 58,106 मैट्रिक टन कन्स्ट्रक्शन-डिमोलिशन वेस्ट का कलेक्शन हुआ है। यह वेस्ट डंपिंग साइट पर जाने की बजाय इसकी रीसाइक्लिंग की गई है।

इस प्लांट में ईंट, कंक्रीट, लोहे के टुकड़े एकत्र कर साइंटिफिक प्रोसेसिंग से उन्हें पुनः उपयोगी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्रश्ड एग्रीगेट्स, रिसाइकल्ड रेती, पेवर ब्लॉक तथा कंक्रीट, ईंटों जैसी गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की जाती है।

करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार व्हील ऑफ फॉर्च्यून पर वापस लेकर आए 90 के दशक का जादू

मुंबईः व्हील ऑफ फॉर्च्यून दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, और जब बॉलीवुड दिवा करिश्मा कपूर, अनु मलिक और मौनी रॉय के साथ शो में आईं, तो उत्साह का स्तर कई गुना बढ़ गया। अक्षय कुमार द्वारा होस्ट किया गया यह एपिसोड सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर पुरानी यादों, हंसी और पूरे मनोरंजन से भरी एक यादगार यात्रा बन गया। पुरानी यादें तब और गहरी हो गई, जब अक्षय ने एक दिल छू लेने वाला पल शेयर करते हुए कहा, "जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह मेरी पहली हीरोइन हैं। मैंने उनके साथ अपनी पहली फिल्म, अपना पहला गाना किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितनी खूबसूरत हैं।" करिश्मा ने गर्मजोशी से जवाब दिया, "धन्यवाद।" जश्न यहीं नहीं रुकता। यह आइकॉनिक जोड़ी फिल्म दीदार के 34 साल पूरे होने पर अपने यादगार गाने 'दीदार हो गया मुझको प्यार हो गया' को फिर से स्टेज पर पेश करके जादू बिखेरती है और फैंस को

रोमांचित कर देती है। एक और प्रोमो में उनकी चंचल दोस्ती को दिखाया गया है, जिसमें अक्षय मजाक में कहते हैं, "बांद्रा में हर बिल्डिंग के अंदर इनके एक-एक फ्लैट हैं," जिस पर करिश्मा तुरंत जवाब देती हैं, "कुछ भी!" इस मजाक में शामिल होते हुए अनु मलिक कहते हैं, "अक्षय कभी झूठ नहीं बोलते," जबकि करिश्मा चिढ़ाते हुए पलटवार करती हैं, "तुम्हें पता है, वह पूरे जुहू के मालिक हैं!" अक्षय बात को और आगे बढ़ाते हुए लिस्ट में सांताक्रूज और खार को भी जोड़ देते हैं, जिससे लगातार हंसी का माहौल बना रहता है। पुरानी यादों, हास्य और अपनी आइकॉनिक दोस्ती के साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यह एपिसोड दर्शकों के लिए एक पूरा एंटरटेनर होने का वादा करता है। अक्षय कुमार द्वारा होस्ट किया जाने वाला व्हील ऑफ फॉर्च्यून 27 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9:00 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रसारित होगा

'भारत में इस समय किसी भी...', यूजीसी के नए नियमों पर रउ के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने मोदी सरकार को किया अगाह

((जीएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहा देश-व्यापी सियासी और अकादमिक घमासान फिलहाल थम सा गया है। अदालत ने 17 दिन पहले लागू किए गए इन नियमों पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अंतरिम अवधि में वर्ष 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। हालांकि, सवाल अब भी कायम है कि यह राहत अस्थायी है या आने वाले समय में यह मामला और अधिक तीखे मोड़ पर पहुंच सकता है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल रोक लगाए जाने के बाद मशहूर कवि और राम कथावाचक कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया आई है। याद रहे दो दिन पहले कुमार विश् वास ने एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर यूजीसी के नए नियम पर विरोध जताया था। जानिए कुमार विश्वास ने सुप्रीम के फैसले के बाद क्या ऐसा कहा जिसकी चर्चा हो रही है?

कुमार विश्वास ने मोदी सरकार

को किया अगाह

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुमार विश्वास ने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सरकारों और राजनीति को विभाजक रेखाएँ खींचने से बचना चाहिए। विश्वास ने स्वीकार किया कि दलित, पिछड़े और वंचित मित्रों के साथ सदियों से बहुत अत्याचार हुआ है।

'सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों लोगों की मनोदशा का भाव समझा'

विश्वास ने अपने बयान में आगे कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों लोगों की मनोदशा का भाव समझा।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'यह भी कहने में लोगों की जबान हकलाती है कि ये सब जो पिछले एक हजार वर्षों में विधर्म भारत में आया था, जिनके यहां परंपराएं थीं, उन्होंने ये भारत में बोया था।'

कुमार विश् वास बोले- 'विधर्म' से मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं...

कुमार विश् वास के अनुसार इस 'विधर्म' से मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं, जो पिछले 80 वर्षों से जारी हैं और आगे भी होंगे। उन्होंने जोर दिया कि इस प्रक्रिया में कोई निरपराध व्यक्ति न फँसे, और न ही किसी जाति, वर्ण या धर्म का व्यक्ति असहज महसूस करे। विश्वास ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और उम्मीद जताई कि राजनीति भी इसका सकारात्मक हल निकालेगी।

कुमार विश्वास ने यूजीसी के नए नियम के विरोध में लिखी था- रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा ..।

गौरतलब है कि दो दिन पहलेकवि कुमार विश्वास ने #UGC_RollBack हैशटैग के साथ यूजीसी नियमों पर अपना विरोध जताते हुए उन्होंने दिवंगत कवि रमेश रंजन की एक कविता साझा की, जिसकी पंक्तियाँ हैंः "चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोंया रोंया उखाड़ लो राजा.."!

कौलाछापर के ट्रॉफी पर एसएन मेमोरियल ने जमाया कब्जा

कौला छापर में आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल ट्रॉफी के साथ विजेता टीम

देवरिया ।देसही देवरिया के कौला छापर में आयोजित राज्य स्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता का रंगारंग समापन बुधवार की रात हुआ। एसएन मेमोरियल ने प्रतियोगिता पर कब्जा जमा लिया। एसएन के खिलाड़ी मज को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया।

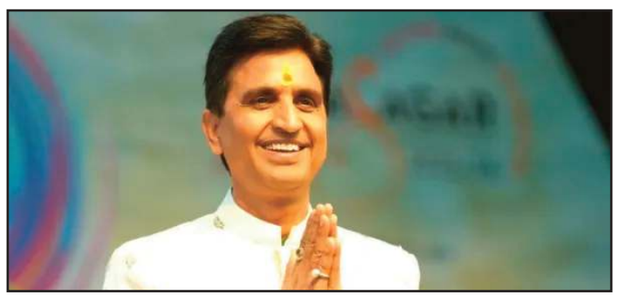

देर रात जुगनू स्पोर्ट क्लब कौलाछापर पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच एसएन मेमोरियल पब्लिक स्कूल और नौशाद वाराणसी के बीच खेला गया। एसएन ने पहला सेट 13-15 से जीता तो वहीं नौशाद वाराणसी की टीम के प्लेयर विकास ने खेल के अच्छे प्रदर्शन करते हुए दूसरा सेट 15-14 से अपने नाम कर लिया। एसएन के बेस्ट प्लेयर मज ने अपने दम पर दोनों सेट लगातार 16-15 और 15 -14 से जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। यूपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट धर्मेश कुमार शाही डिप्टी एसपी एसटीएफ लखनऊ मुख्यालय खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल प्रति जागरूक किए। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि देसही देवरिया इंजीनियर संजय तिवारी विशिष्ट भाजपा नेता सुनील राव के प्रतिनिधि गौरव मारी त्रिपाठी ने विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी वितरित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष आफताब आलम ने अतिथियों को अंग वस्त्र व माला पहनकर फील्ड में स्वागत किया। रेफरी ब्यास चतुर्वेदी और अमित बच्चन रहे। सचिव ग्राम प्रधान मोहम्मद रफी खान ने सभी खिलाड़ियों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस दौरान, अब्दुल रहमान, बेलाल अहमद, मोहम्मद रिजवान खान, हसनैन खान, सदरूद्दीन, गुलाम हैदर, साद, प्रबंधक रियाज खान, इन्फोटेक के डायरेक्टर रफीउल्लाह, खान, बसीर, सैफ, ग्राम प्रधान मोहम्मद फखरुद्दीन खान, हैदर वारिस, डॉक्टर सीटू, मैनुद्दीन खान उर्फ सोनू, मिराज खान, शाहिद खान, आदि उपस्थित रहे।

सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोकिंग कोयले को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया

((जीएनएस)।

खनन क्षेत्र में जारी संरचनात्मक सुधारों के अंतर्गत और आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के अंतर्गत कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है।

यह निर्णय विकसित भारत लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-वीबी) की सिफारिशों और नीति आयोग से प्राप्त नीतिगत सुझावों के आधार पर लिया गया है, जिसमें खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और घरेलू इस्पात क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोकिंग कोयले की रणनीतिक भूमिका को मान्यता दी गई है।

भारत में अनुमानित 37.37 अरब टन कोकिंग कोयले का भंडार है, जो मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी भंडार मौजूद हैं। घरेलू स्तर पर इतनी उपलब्धता के बावजूद, कोकिंग कोयले का आयात 2020-21 में 51.20 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 57.58 मिलियन टन हो गया है। वर्तमान में, इस्पात क्षेत्र की कोकिंग कोयले की लगभग 95 प्रतिशत आवश्यकता आयात से पूरी होती है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का व्यय होता है।

इस निरंतर निर्भरता को दूर करने के लिए, केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11सी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया है। तदनुसार, भाग अ में "कोयला" शब्द को अब "कोकिंग कोयला सहित कोयला" के रूप में पढ़ा जाएगा, और "कोकिंग कोयला" को भाग घ में शामिल किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची है।

इस श्रेणी में कोकिंग कोयले को शामिल करने से अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आने, व्यापार करने में सुगमता बढ़ने और गहरे भंडारों सहित अन्वेषण एवं खनन गतिविधियों में गति आने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता से मुक्त रखा गया है और इससे क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए खराब हो चुकी वन भूमि के उपयोग की अनुमति मिलती है। इन उपायों से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

इस सुधार से आयात पर निर्भरता कम होने, इस्पात क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ने और राष्ट्रीय इस्पात नीति के उद्देश्यों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, इससे अन्वेषण, शोधन और उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में निजी निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ खनन, रसद और इस्पात मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन होने की भी उम्मीद है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11डी (3) के अनुसार, रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम और खनन पट्टों से संबंधित अन्य वैधानिक भुगतान संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होते रहेंगे, भले ही खनिज नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती हो।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

यूजीसी 2026 बिल मामला : जानिए कौन सी हैं वो दलीलें जिनसे कोर्ट हुआ सहमत

((जीएनएस)।

उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए वक्फ़ इ'' 2026 पर अब शीर्ष अदालत ने ब्रेक लगा दिया है। अदालत ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया, जिनमें 2026 के नियमों को गैर-समावेशी, मनमाना और संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया था।

कोर्ट ने इन नियमों के प्रवर्तन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले की संवैधानिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक शिक्षण संस्थानों में 2012 के पुराने दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे।

विस्तार से जानते हैं कि कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से क्या-क्या दलीलें पेश कि गईं, कोर्ट ने क्या कहा...

अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा दायर याचिकाओं में 2026 के नियमों को "मनमाना" करार दिया गया। कोर्ट में दी गई मुख्य दलीलें इस प्रकार थीं:

सुरक्षा का अधिकार केवल एक वर्ग को क्यों?

याचिकाकताओं ने तर्क दिया कि भेदभाव की परिभाषा को केवल

SC/ST/OBC तक सीमित करना गलत है। सामान्य श्रेणी के छात्र भी जातिगत शत्रुता या दुर्व्यवहार का शिकार हो सकते हैं, जिन्हें इस कानून ने सुरक्षा से वंचित कर दिया है।

अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघनः

दलील दी गई कि यह कानून एक "प्रतिकूल वर्गीकरण" पैदा करता है, जो संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के विरुद्ध है।

रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन (विपरीत भेदभाव):

याचिकाओं में कहा गया कि यह कानून इस एकतरफा धारणा पर टिका है कि भेदभाव केवल एक ही दिशा में होता है, जबकि सवर्ण छात्रों के साथ होने वाले उत्पीड़न की संभावना को पूरी तरह अनदेखा किया गया है।

सरकार और UGC का क्या था पक्ष?

वहीं, भारत सरकार और यूजीसी ने अदालत में 2026 के नियमों का बचाव करते हुए कहा कि ये विनियम ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों की जमीनी सच्चाइयों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। सरकार ने दलील दी कि यह कदमरोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं द्वारा दायर एक पुरानी जनहित याचिका (ढक्छ) के संदर्भ में उठाया गया था।

उन मामलों ने यह उजागर किया था कि संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के कारण छात्रों को गंभीर मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलनी पड़ी। सरकार के अनुसार, 2026 के नियम सलाहात्मक नहीं बल्कि बाध्यकारी (enforceable) व्यवस्था लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे, ताकि संस्थानों को जवाबदेह बनाया जा सके।

रउ की तल्ख टिप्पणीः "हम जानते हैं क्या हो रहा है"

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, "हम जानते हैं कि क्या हो रहा है।" पीठ ने माना कि सुरक्षा का ऐसा कोई 'पदानुक्रम' (HierÔrchy) नहीं बनाया जा सकता जो छात्र आबादी के किसी भी एक वर्ग को सुरक्षा तंत्र से बाहर कर दे। कोर्ट ने रेगुलेशन 3(c) की संकीर्णता को

गिर के जंगल और समूचे लायन लैंडस्केप सहित अन्य वन क्षेत्रों के वन कर्मियों को मिलेंगे विशेष सुविधाओं से सुसज्जित वाहन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सासण गिर में वन कर्मियों के लिए 183 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

गांधीनगर, 29 जनवरी : वन संपदा और वन्य जीव सृष्टि के मामले में समृद्ध गुजरात में वन्य प्राणी संरक्षण, संवर्धन, रेस्क्यू और पुनर्वास जैसे विभिन्न कार्यों के लिए फील्ड में कार्यरत वन कर्मियों को निश्चित प्रकार की विशेष सुविधाओं से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार सुबह सासण गिर में ऐसे 183 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

वन विभाग ने विभिन्न प्रोजेक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ की

पेट्रोलिंग, प्रोटेक्शन और रेस्क्यू जैसे कार्यों के लिए 174 फील्ड बाइक, 6 बोलेरो कैम्पर और 3 मॉडिफाइड रेस्क्यू वाहन उपलब्ध कराए हैं।

इन वाहनों को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री सवेरे शेर दर्शन के लिए गए। उन्होंने अपने दिन की शुरूआत गिर के जंगल में शीत ऋतु की ठंडक के साथ प्रकृति के खुशनुमा सान्निध्य में की और शेर दर्शन की रोमांचक अनुभूति की।

मुख्यमंत्री द्वारा विशेष सुविधाओं से लैस इन वाहनों को संबंधित वन कर्मियों को आवंटित करने के लिए हरी झंडी दिखाने के अवसर पर वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. विनोद राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. जयपाल सिंह और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर का भी दौरा किया।

ये नए वाहन गिर, बृहद गिर और समूचे लायन लैंडस्केप सहित राज्य के अन्य वन क्षेत्रों के वन कर्मियों के लिए और भी कुशलतापूर्वक कार्य करने के साथ-साथ रेस्क्यू के कार्य में भी उपयोगी सिद्ध होंगे।

स्वर्गीय सहदेव माली की स्मृति में तहरी भोज

प्रेस क्लब में उमड़ा पत्रकारिता और राजनीति का संगम,

लखनऊ। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सहदेव माली की स्मृति में यू०पी० प्रेस क्लब एवं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट

यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में प्रेस क्लब परिसर में आयोजित तहरी भोज कार्यक्रम भावपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और पत्रकारिता जगत की जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत कर स्व० सहदेव माली को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप, प्रदेश सचिव दीपक रंजन, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे, पूर्व राज्यसभा सदस्य अरविंद सिंह, इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी, प्रदेश महामंत्री मुकेश सिंह चौहान एवं प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी, महामंत्री देवराज सिंह, लखनऊ इकाई के अध्यक्ष शिव शरण सिंह तथा यू०पी० प्रेस क्लब के अध्यक्ष रविंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकारों, संवाददाताओं एवं सामाजिक कार्यकताओं ने सहभागिता की।

वक्ताओं ने स्वर्गीय सहदेव माली के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे पत्रकारिता के मूल्यों—सत्य, साहस और निष्पक्षता—के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि स्व० माली ने अपने पूरे जीवन में पत्रकारिता को मिशन के रूप में अपनाया और आमजन की आवाज को मजबूती से मंच प्रदान किया।

अज्ञात बदमाशों ने 35 भेड़ों को किया पार, मुकदमा पंजीकृत

खखरेरू/फतेहपुर थाना क्षेत्र के बरैयपुर गांव के पास बनी पानी टंकी के समीप अज्ञात बदमाशों ने रात्रि के अंधेरे में चरवाहों की 35 भेड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद निवासी खैरई गडरियन का पुरवा एवं वीरेंद्र निवासी नसीरपुर अपनी भेड़ों को चराने के लिए खंतवा की ओर गए हुए थे। वापसी के दौरान अंधेरा हो जाने के कारण दोनों चरवाहे बरैयपुर गांव के किनारे बनी पानी टंकी के पास भेड़ों को बैठाकर खाना-पीना खाकर वहीं सो गए।

पीड़ितों के अनुसार रात्रि लगभग 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात बदमाश एक पिकअप वाहन से मौके पर पहुंचे और 35 भेड़ों को वाहन में लादकर फरार हो गए। चरवाहों ने बताया कि उनके पास कुल 140 भेड़ें थीं, जिनमें से 35 भेड़ों को बदमाश ले गए।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस द्वारा संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। इस मामले में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

इस संबंध में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है तथा जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैक पार रहीं दो महिला ट्रेन की चपेट में आई, कटकर हुई मौत

-सिर पर लकड़ी रखकर पार कर रहीं थी ट्रैक

((जीएनएस)।

फतेहपुर। रेलवे लाइन पार करते समय दो महिलाओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों जंगल से लकड़ी काटकर सिर पर रखे रेलवे ट्रैक पार कर रही थीं। उसी समय अचानक तेज रफ्तार ट्रेन के आ जाने पर चपेट में आ गईं।

एकारी गांव निवासी रामभवन रैदास की पत्नी शोभा देवी(40) और मोहल्ले की ही स्वर्गीय अर्जुन पासवान की पत्नी श्यामकली(45) गुरुवार शाम लकड़ी काटने जंगल गईं थीं। एक बार लकड़ी लेकर घर पर रख आईं, पुनः लकड़ी लेकर वह लोग ट्रैक पार रहीं थीं अचानक कानपुर की तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गईं, इससे कटकर दोनों की मौत हो गई। मृतका श्यामकली के पति स्वर्गीय अर्जुन पासवान रेलवे कर्मचारी थे, उनकी मौत भी ट्रेन हादसे से हुई थी।

गोविंदनगर पुलिस ने फरार आरोपी पकड़ा : अवैध हथियार बरामद

मथुरा ((जीएनएस)। थाना गोविन्दनगर क्षेत्र स्थित आजमपुर मोड़ के पास से पुलिस ने वांछित चल रहे आरोपी को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी गोविंदनगर रवि त्यागी और चौकी प्रभारी मसानी महेन्द्र सिंह पुलिस टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में जुटे हुए थे।

उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि आदमपुर मोड़ के पास वांछित चल रहा एक आरोपी खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रवि त्यागी और चौकी प्रभारी महेन्द्र सिंह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे वांछित आरोपी साहिल शाह पुत्र सैय्यद साबिर निवासी मदीना मस्जिद के पास, नवनीत नगर थाना कोतवाली, मथुरा को घेरकर पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है।

हिण्डाल्को रेनुसागर में त्रैवार्षिक वेतन समझौता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न

अनपरा (सोनभद्र)। हिण्डाल्को रेनुसागर में प्रबंधन एवं श्रमिक संगठनों के बीच त्रैवार्षिक वेतन समझौता सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक एवं आपसी सहमति के वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

हिण्डाल्को रेनुसागर की मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों तथा प्रबंधन के मध्य त्रैवार्षिक वेतन समझौता बीते 27 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो गया। श्रम संगठनों ने श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य मांगों के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रबन्धन को प्रस्तुत किया था और उभय पक्षों के मध्य विभिन्न तिथियों पर हुई कई चक्रों की वार्ता के पश्चात हिण्डाल्को रेनुसागर के टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह समझौता सम्पन्न हुआ।

इस समझौते पर प्रबंधन की ओर

से हिण्डाल्को रेनुसागर के यूनिट हेड आर पी सिंह, मानव संसाधन प्रमुख रेनुसागर आशीष कुमार पांडेय,संचालन विभाग के प्रमुख मनीष जैन , वित्त एवं वाणिज्य प्रमुख नवींद्र पाठक,ईआर हेड मृदुल भारद्वाज तथा मान्यता प्राप्त श्रम संगठन पदाधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

उक्त अवसर पर हिण्डाल्को रेणुकूट के क्लस्टर हेड समीर नायक एवं हिण्डाल्को रेणुकूट के क्लस्टर एच.आर. हेड जसबीर सिंह ने संयुक्त रूप से सुव्यवस्थित रूप से निष्पादित समझौते को लेकर श्रमिक संगठनों एवं प्रबंधन पक्ष को बधाई दी। इस अवसर पर हिण्डाल्को रेनुसागर के यूनिट हेड आरपी सिंह ने कहा कि पारदर्शी संवाद, विश्वास और सहयोग से श्रमिक हित में वेतन वृद्धि सहित कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वही हेड एच आर आशीष पांडेय ने समझौते के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सरल एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हुए विस्तृत जानकारी साझा की, जिसकी यूनियन पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एकमत से सराहना की।

शराबबंदी के लिए राष्ट्रीय मोर्चा की हुंकार--मुर्तजा अली

लखनऊ में राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा और शराबबंदी संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में भारत के विभिन्न प्रदेशों से कार्यकताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आर्य प्रतिनिधि सभा में आयोजित इस सम्मेलन में आर्य समाज के प्रधान देवेंद्र कुमार वर्मा जी ने अध्यक्षता की और सुलतान सिंह संयोजक रहे।

इस सम्मेलन में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने की तैयारी की गई है, जिसमें मुख्य पार्टियों से शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की जाएगी। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है, जिसमें शराबबंदी की मांग की जाएगी ८।

सम्मेलन में शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चा की गई और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए रणनीति बनाई गई है। शराबबंदी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य शराबबंदी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना और इसे मुख्य पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करवाना है।

इस सम्मलेन में मुख्या तौर पर विभिनं प्रदेशों से आये जिनमे मुर्तजा अली राष्ट्रीय अध्यक्ष शराब बंदी संघर्ष समिति, श्री पी, सी, कुरील भागीदारी आंदोलन , श्री राज कुमार सिंह, (नेशनल युथ पार्टी, इशरत बेग, साद बेग, हलीमा अजीम, फैजुद्दीन सिद्दीकी,फहद हसन, इमरान शेख, मो. कैफ , वाणी दस उड़ीसा से, कल्याणी जी पश्चिम बंगाल से, सुभेन्द्रू जी उड़ीसा से, जीवन चंद्र उत्प्रेती उत्तराखंड से, हरी ॐ गौतम मध्य प्रदेश से, वर्षा विद्या विलास महाराष्ट्र से सम्मिलित हुईं'

गुलरिया चीनी मिल ने महिला थाने को गिफ्ट किया वाटर कूलर

बिजुआ।बलरामपुर फाउंडेशन के तहत गुलरिया चीनी मिल ने सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योजना के तहत शहर के महिला थाने को एक आरओ प्रणाली युक्त वाटर कूलर प्रदान किया है। इसका उद्देश्य थाने में आये फरियादियों के साथ पुलिसकर्मियो को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है।

गुलरिया चीनी मिल के यूनिट हेड योगेश कुमार सिंह की पत्नी बबिता सिंह ने इसका उद्घाटन फीता काटकर किया। यह वाटर कूलर 150 लीटर क्षमता का है।

महिला थाने की एसओ ने मुख्य अथिति को अंगवस्त्र व बुके देकर स्वागत किया।

इस दौरान चीनी मिल के अभिनेष मिश्रा,महिला थाने का स्टाफ मौजूद था।

यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का स्वागत

: न्यायालय की टिप्पणियां लोकतांत्रिक, समावेशी एवं एकताबद्ध समाज की दिशा में अहम: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ईक्विटी रेगुलेशन वापस लेने की मांग

लखनऊ। सामाजिक समरसता मंच, ने UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों एवं निदेशों का स्वागत करते हुए कहा है कि ये टिप्पणियां न केवल शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता और समावेशिता की रक्षा करती हैं, बल्कि भारतीय समाज की एकता और सामाजिक सौहार्द को भी मजबूती प्रदान करती हैं।

मंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां यह स्पष्ट करती हैं कि सामाजिक न्याय के नाम पर ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जो समाज में नए विभाजन पैदा करें। मंच ने मांग की कि केंद्र सरकार और वक्फ़ न्यायालय की टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए नियमो को तत्काल वापस ले ।

मंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वक्फ़ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लागू न किया जाए। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इन नियमों को ह्लअस्पष्टह्व बताते हुए इनके दुरुपयोग की आशंका जताई है, जो इस बात का प्रमाण है कि नियमों को बिना व्यापक विमर्श के लागू करना उचित नहीं है।

मंच ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का भी स्वागत किया कि

इन नियमों की पुनर्समीक्षा एक छोटी समिति द्वारा की जाए, जिसमें प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल हों, ताकि नियम संविधान की भावना, सामाजिक न्याय और व्यावहारिक वास्तविकताओं के अनुरूप हों ।

मंच के अनुसार न्यायालय द्वारा उठाए गए निम्नलिखित प्रश्न अत्यंत गंभीर एवं दूरगामी महत्व के हैं—

क्या ऐसे मामलों में भी भेदभाव माना जाएगा, जहाँ जातिगत पहचान स्पष्ट न हो, जैसे भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर अपमान?

नियमों में यह मानकर क्यों चला गया है कि उत्पीड़न केवल जाति-आधारित ही होता है, जबकि व्यवहार में अन्य आधारों पर भी भेदभाव और उत्पीड़न होता है?

क्या इस प्रकार के नियमों से हम जातिविहीन समाज की दिशा में अब तक की गई प्रगति से पीछे नहीं जा रहे हैं?

मंच ने सुप्रीम कोर्ट की उस सशक्त टिप्पणी को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, जिसमें अलग-अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल की अवधारणा पर न्यायालय ने कहा—

ह्लभगवान के लिए, ऐसा मत कीजिएह्व हम सब साथ रहते थे।ह्व

मंच ने कहा कि यह टिप्पणी भारत की साझा संस्कृति, भाईचारे और सामाजिक समरसता की आत्मा को दशार्ती है।

मंच ने इस बात से भी सहमति जताई कि शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए, न कि ऐसे प्रावधान हों जो समाज को और अधिक खांचों में बांटें।

न्यायालय द्वारा यह प्रश्न उठाया जाना भी महत्वपूर्ण है कि जब रेगुलेशन 3(1) पहले से ही भेदभाव को कवर करता है, तो रेगुलेशन 3() की आवश्यकता क्यों है—क्या यह अनावश्यक नहीं है? साथ ही यह भी कि यदि 2012 के नियम अधिक समावेशी थे, तो 2026 में उनसे पीछे क्यों जाया जा रहा है और रैगिंग जैसे गंभीर मुद्दे को नियमों में क्यों नहीं शामिल किया गया।

सामाजिक समरसता बनाए रखने हेतु यह मंच समाज में व्यापक जनसंपर्क और बैठकों का अभियान जारी रखेगा।

सामाजिक समरसता मंच की आज आशियाना मे हुई बैठक में मुख्यतया रीना त्रिपाठी, सीमा द्विवेदी, रेनू त्रिपाठी, देवेन्द्र शुक्ल, अजय तिवारी, सुरेश चन्द्र बाजपेई, दुर्गेश पांडे, प्रेम तिवारी, सुधांशु मिश्र, शिव दीक्षित, संजय कुमार द्विवेदी , अनिल सिंह उपस्थित थे।

गुजरात साइंस सिटी में 77वें गणतंत्र दिवस का गौरवपूर्ण आयोजन

लखनऊ, 29 जनवरी 2026: अहमदाबाद स्थित गुजरात साइंस सिटी में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस का गौरवमय एवं प्रेरणादायक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्रीमती पी. भारती, आईएएस के करकमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान की गूंज के साथ संपूर्ण परिसर देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से ओतप्रोत हो गया।

इस अवसर पर श्रीमती पी. भारती ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों के साथ-साथ विज्ञान और नवाचार को राष्ट्रीय प्रगति का सशक्त आधार बनाने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने आगे कहा कि यह वर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है क्योंकि 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव भी मनाया जा रहा है। 'वंदे मातरम्' केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रजागरण और सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। आज यही भावना हमारी प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, स्टार्टअप्स और नवाचार केंद्रों में सजीव रूप में दिखाई देती है। 21वीं सदी में विज्ञान राष्ट्र की शक्ति है—यह स्वास्थ्य की रक्षा करता है, पर्यावरण का संरक्षण करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है और युवाओं को सशक्त बनाता है। गुजरात आज नवीन तकनीकों, परियोजनाओं और वैज्ञानिक ऊर्जा के साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अग्रेसर है।

इस अवसर पर गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी के कार्यकारी निदेशक श्री विमल के. पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत का संविधान समाज को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने में गुजरात साइंस सिटी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

इस समारोह में अधिकारी, कर्मचारी, आमंत्रित अतिथि एवं बड़ी संख्या में आगंतुक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संवैधानिक मूल्यों का स्मरण किया गया तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का उत्सव मनाया गया।

गुजरात साइंस सिटी द्वारा आयोजित यह गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रप्रेम, वैज्ञानिक चेतना और युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा जगाने वाला सिद्ध हुआ।

पद्मश्री से अलंकृत होने पर वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल रस्तोगी का हरिश्चन्द्र वंशीय समाज की ओर से सम्मान

लखनऊ। लखनऊ हरिश्चन्द्र वंशीय समाज की ओर से बृहस्पतिवार को पद्मश्री से अलंकृत होने पर वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल रस्तोगी को सम्मानित किया गया। डा. रस्तोगी के आवास पर हुए सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे समाज के अध्यक्ष राजन रस्तोगी, रस्तोगी स्वास्थ परीक्षण समिति के अध्यक्ष दीपक, दर्पण समिति के अध्यक्ष गिरीश, स्टार्टअप के अध्यक्ष सुधांशु, लखनऊ समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव, महामंत्री प्रदीप एवं संरक्षक हरी जीवन रस्तोगी ने डॉक्टर अनिल रस्तोगी को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर डा. अनिल रस्तोगी ने समाज से जुड़ी यादों को साझा करते हुए कहा कि अभिनय के क्षेत्र में वह बचपन में रस्तोगी समाज द्वारा किए जा रहे थियेटर में अभिनय की शुरूआत की। इसके बाद रंगमंच से लेकर अनेक फिल्मों तक काम किया। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्री चंद्र किशोर रस्तोगी ने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया आज मैं जो भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ वह बड़े भाई की प्रेरणा से ही संभव हुआ है । प्रदीप रस्तोगी महामंत्री लखनऊ हरिश्चंद्र वंशीय समाज

द जैन इंटरनेशनल स्कूल, मैनावती मार्ग के छात्र-छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा किया

कानपुर। जनपद स्थित द जैन इंटरनेशनल स्कूल, मैनावती मार्ग के छात्र-छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से शिष्टाचार भेंट की और उनसे संसदीय कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।

विधानसभा अध्यक्ष श्री महाना ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि ऐसे शैक्षणिक भ्रमण छात्रों में लोकतंत्र, संविधान और संसदीय परंपराओं के प्रति समझ और जागरूकता बढ़ाते हैं। उन्होंने छात्रों को भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया।

इस भ्रमण के दौरान छात्रों ने विधानसभा की कार्यवाही, सदन की संरचना एवं विधायी प्रक्रिया को निकट से देखा, जिससे उनका ज्ञानवर्धन हुआ। विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने इस शैक्षणिक यात्रा को छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बताया।

विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से सोचते हैं आईआईटी दिल्ली के छात्र : रुम्मान

बतौर ज्यूरी सदस्य प्रतिभाग करने को बताया गौरव

पीलीभीत। देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में आयोजित एक नवाचार आधारित कार्यक्रम में बतौर ज्यूरी सदस्य शामिल हुए मोहम्मद रुम्मान ने कहा कि यहां के छात्र विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण रूप से तेजी से सोचने की क्षमता रखते हैं। विचारों के मूल्यांकन से लेकर पिच राउंड के दौरान टीमों के साथ संवाद तक यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि छात्र केवल तकनीकी दक्षता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे बिल्डर, नवाचारक और शुरूआती उत्पाद-विचारक के रूप में भी परिपक्व सोच रखते हैं, जो उपयोगकताओं की वास्तविक समस्याओं को समझते हैं।

उन्होंने कहा कि निर्णायक मंडल और प्रतिभागी छात्रों के बीच हुई बातचीत केवल आलोचनात्मक विश्लेषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें मंचीय घबराहट से निपटने, प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान उत्तरों को व्यवस्थित करने, दबाव की परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने और स्पष्ट निर्णय लेने जैसे अहम विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। 19झ्र20 वर्ष के युवाओं को इतने आत्मविश्वास, स्पष्टता और परिपक्वता के साथ अपने विचार प्रस्तुत करते देख यह अनुभव हुआ कि यदि सही माहौल मिले, तो शुरूआती अनुभव भी वर्षों के ज्ञान के बराबर हो सकते हैं।

उन्होंने आईआईटी दिल्ली की आयोजन टीम का प्रोडक्ट फोक्स को आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया तथा निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों का भी हृदय से धन्यवाद दिया।

शहर के मोहल्ला शेर मो. निवासी समाजसेवी व कातिब नासिर कमाल के भांजे, श्री एवं श्रीमती फरहत अकील अहमद के पुत्र मो. रुम्मान ने कहा कि उस स्थान पर दोबारा लौटना, जहाँ कभी अपनापन महसूस करने का सपना देखा था, लेकिन अब बिल्कुल अलग भूमिका में—यह अनुभव शब्दों से परे है। यह जीवन के उन दुर्लभ क्षणों में से एक है, जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है।

उन्होंने कहा कि अनगिनत भारतीय इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों की तरह आईआईटी दिल्ली भी उनके लिए तैयारी के दिनों में एक सपनों का संस्थान था। आज उन्हीं गलियारों में एक अभ्यर्थी के रूप में नहीं, बल्कि वक्ता और निर्णायक के रूप में चलना गर्व और आत्ममंथन से भरा अनुभव रहा। जीवन का अपना एक अनोखा गणित होता है—वह व्यक्ति को उन्हीं स्थानों पर वापस ले आता है, जिन्होंने कभी उसके सपनों को दिशा दी थी।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में से विजेता छात्रों का चयन कर उन्हें सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य और प्रेरणादायक अनुभव रहा।

अजीत पवार: सत्ता के गलियारों में इंसाफ की आवाज खामोश – एक असमय विदाई!

सैय्यद जलालउद्दीन
नेशनल जनरल सेक्रेटरी
एन - सी - पी (अजीत पवार)
(नेशनल चेयरमैन माइनारटीज)
एन - सी - पी (अजीत पवार)

महाराष्ट्र की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहाँ शोक केवल एक व्यक्ति के जाने का नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक संतुलित दृष्टि और एक साहसी नेतृत्व के खामोश हो जाने का है। विमान दुर्घटना में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के असामयिक निधन की खबर ने न केवल महाराष्ट्र, बल्कि देश के हर उस नागरिक को स्तब्ध कर दिया है, जो राजनीति को केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम मानता है।

राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, विचारधाराएँ टकराती हैं, गठबंधन बनते-टूटते हैं—लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनकी मौजूदगी मतभेदों के बीच भी भरोसे की एक रेखा खींचती है। अजीत पवार उन्हीं व्यक्तित्वों में से एक थे।

एक दृढ़ लेकिन संवेदनशील नेतृत्व

अजीत पवार को अक्सर एक कठोर, स्पष्टवादी और प्रशासनिक दक्षता से भरपूर नेता के रूप में देखा गया। वे निर्णय लेने में देर नहीं करते थे और न ही अपनी बात कहने में संकोच। लेकिन इस दृढ़ता के भीतर एक ऐसा पक्ष भी था, जो कम बोलता था समाज के हाशिये पर खड़े लोगों के लिए उनकी संवेदनशीलता।

यही कारण था कि वे केवल अपने समर्थकों के नेता नहीं रहे, बल्कि उन समुदायों के लिए भी भरोसे का नाम बने, जिनकी आवाज अक्सर सत्ता के शोर में दब जाती है।

आज जब देश की राजनीति में ह्लसेकुलरिज्महृ एक विवादित शब्द बनता जा रहा है, अजीत पवार ने इसे नारे में नहीं, नीति में उतारा। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता कोई भाषण का विषय नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा थी।

विशेषकर महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी, जिसने केवल सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुँचाने का काम किया।

अजीत पवार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं को न केवल जारी रखा गया, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू कराया गया। इनमें प्रमुख रूप से—

1. मदरसा आधुनिकीकरण और शिक्षक मानदेय

मदरसा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि कर उन्होंने यह संदेश दिया कि धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षक भी सम्मान और सुरक्षा के अधिकारी हैं। यह फैसला केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि सामाजिक सम्मान से जुड़ा था।

2. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएँ

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के माध्यम से हजारों मुस्लिम छात्रों को पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिला। कई परिवारों के लिए यह सहायता बच्चों के भविष्य और ड्रॉप-आउट रोकने का आधार बनी।

3. हज समिति और वक़्फ़ से जुड़े प्रशासनिक सुधार

हज यात्रियों की सुविधाओं, वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता पर भी उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर संतुलित रुख अपनाया।

इन सभी प्रयासों में खास बात यह थी कि उन्होंने कभी इन योजनाओं को राजनीतिक प्रचार का हथियार नहीं बनाया।

बीजेपी के साथ सत्ता, लेकिन आत्मा स्वतंत्र

यह एक राजनीतिक सच्चाई है कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उपमुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन को लेकर उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि मुस्लिम मुद्दों पर उन्होंने कभी समझौते की भाषा नहीं बोली।

जहाँ जरूरत पड़ी, उन्होंने स्पष्ट कहा किह्लकानून सबके लिए बराबर है, और महाराष्ट्र में किसी भी समुदाय के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा।ह्व यह साहस आसान नहीं होता—खासकर तब, जब राजनीति ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही हो।

बारामती केवल उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, बल्कि उनकी पहचान और कर्मभूमि थी। वहाँ की गलियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं से उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं, आत्मीय था।

आज बारामती में जो सन्नाटा है, वह केवल एक नेता की कमी का नहीं—एक अपने के चले जाने का सन्नाटा है।

"विमान दुर्घटना एक अधूरा सफर"

जिस विमान यात्रा को एक नियमित प्रशासनिक दौरा माना जा रहा था, वही उनकी अंतिम यात्रा बन जाएगी—यह किसी ने नहीं सोचा था। हादसा अचानक हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गया सवालों, आँसुओं और एक गहरे खालीपन को।

ये मेरे और उनके परिवार के लिए यह व्यक्तिगत त्रासदी है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए यह राजनीतिक और नैतिक क्षति है। विरोधियों की श्रद्धांजलि, समर्थकों में सन्नाटा पसर गया राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे होते हैं, जिनके जाने पर विरोधी भी सम्मान से सिर झुकाएँ। अजीत पवार उन्हीं में थे।

विवेचना के नाम पर रिश्वत मांगने और मारपीट का पीड़ित भाइयों ने नवाबगंज पुलिस पर लगाया गम्भीर आरोप

प्रयागराज। नवाबगंज थाना क्षेत्र की लालगोपालगंज पुलिस पर एक मुकदमे की विवेचना के दौरान रिश्वत मांगने, मारपीट करने और अभद्र भाषा के प्रयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।

यह आरोप लालगोपालगंज निवासी दो सगे भाइयों—सरफराज और सरवर—ने लगाए हैं, जिन्होंने इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में अपनी आपबीती रखी।

पीड़ित भाइयों के अनुसार, लालगोपालगंज बाजार में उनका मोटर गैरेज है, जहां वे कार रिपेयरिंग का कार्य करते हैं। एक नाली विवाद को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना लालगोपालगंज पुलिस द्वारा की जा रही थी। आरोप है कि

विवेचना के दौरान पुलिस ने उनसे 50 हजार रुपये की मांग की। रकम देने में असमर्थता जताने पर पुलिसकर्मी उनके गैरेज पहुंचे और दोनों भाइयों को वहां से पकड़कर ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई और गाली-गलौज भी की गई। पीड़ितों का कहना है कि मारपीट में सरफराज का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि सरवर बेहोश हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 151 के तहत चालान किया और मेडिकल परीक्षण कराया गया। प्रारंभिक इलाज के बाद चिकित्सक ने उन्हें बेली अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार हुआ।

घटना की जानकारी मिलने पर एसीपी सोरांव भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों के बयान दर्ज किए। सरफराज और सरवर का कहना है कि रिश्वत न देने के कारण ही उनके साथ यह कथित व्यवहार किया गया।

पीड़ित भाइयों का कहना है कि पुलिस अधिकारियों के सामने बयान दर्ज कराने के बाद उन्हें निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब तक संबंधित पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई हुई है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच न्याय की मांग की है।

वहीं, इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोप लगाने वालों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एम0बी0बी0एस0 2025 बैच के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के स्वागत हेतु फ्रेशर पार्टी का गरिमामय आयोजन

दिनांक 28 जनवरी 2026 को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशांबी- ((जीएनएस)। - एम0बी0बी0एस0 2025 बैच के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के स्वागत हेतु फ्रेशर पार्टी का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से परिचित कराना तथा उनके भीतर आत्मविश्वास एवं आपसी समन्वय की भावना विकसित करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो0(डा0) हरिओम कुमार सिंह एवं अतिथिगण श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, सीनियर वित्त अधिकारी, डा0 एस0एन0 सिंह, चेयरमैन, चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान कौशाम्बी एवं डा0 विनोद कुमार गौर, प्राचार्य, चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेदिक संस्थान, कौशाम्बी ने दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया। इसके पश्चात महाविद्यालय के वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिनमें नृत्य, संगीत एवं अन्य मनोरंजक गतिविधियाँ शामिल रहीं। सभी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो0(डा0) हरिओम कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होते हैं तथा संस्थान में सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एम0बी0बी0एस0 वर्ष 2024 बैच के समस्त विद्यार्थियों ने शत प्रतिशत रिजल्ट हासिल किया है, वैसे ही हमे उम्मीद है कि एम0बी0बी0एस0 वर्ष 2025 बैच भी इसी तरह की मेहनत एवं समर्पण के साथ शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। इसके पश्चात सभी नवप्रवेशी विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएँ दीं।

कार्यक्रम का समापन एम0बी0बी0एस0 वर्ष 2024 बैच की छात्रा सेजल ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया, उपस्थित सभी विद्यार्थियों एवं अतिथियों ने कार्यक्रम को अनुशासित, सफल एवं स्मरणीय बताया।

उक्त समारोह में आचार्य डा0 सरस्वती जयसवाल यादव, उप प्रधानाचार्य, डा0 सौरभ कृष्ण मिश्रा ,सह-आचार्य डा0 रविरंजन सिंह, डा0 राकेश कुमार शुक्ला, डा0 अरिन्दम् चक्रवर्ती, डा0 शारदा सिंह, सहायक आचार्य, डा0 धर्मेन्द्र मिश्रा, डा0 संदीप कुमार, डा0 आत्मिक सियंह, डा0 अरूण पाण्डेय, डा0 अंकित कुमार तिवारी, डा0 संतोष कुमार, डा0 नरेन्द्र कुमार, डा0 विकेश कुमार दुबे, डा0 नन्दिनी राघव, डा0 प्रतिमा त्रिपाठी, तथा सीनियर रेजीरेनट व जूनियर रेजीरेनट और कर्मचारी उपस्थित रहे।

दिल्ली से वृंदावन तक शून्य उत्सर्जन प्रकृति जागरूकता रैली पर हुआ मंथन : लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है उद्देश्य

मथुरा ((जीएनएस)। पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से नेचर वेलफेयर काउंसिल द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक प्रस्तावित 135 किलोमीटर की ह्लशून्य उत्सर्जन प्रकृति जागरूकता साइकिल यात्रा के क्रम में वृंदावन में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। दो दिवसीय साइकिल यात्रा कुल 10 अवेयरनेस पॉइंट्स के माध्यम से आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। वृंदावन स्थित रास वीआईपी लाउंज में आयोजित इस इंडक्शन बैठक में संगठन के नव नियुक्त स्टेट चेयरमैन, स्टेट वाइस चेयरमैन और विभिन्न निदेशकों ने भाग लिया। बैठक में यात्रा की रूपरेखा, संगठनात्मक कार्यशैली तथा योजनाओं के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। अभियान के अंतर्गत पांच सौ से अधिक साइकिलिस्टों की सहभागिता और 1 हजार से अधिक युवाओं को पर्यावरणीय संदेश से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए नेचर वेलफेयर काउंसिल के सेंट्रल चेयरमैन राहुल द्विवेदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील विषय में सत्यपरक, प्रमाणिक और

परिणामोन्मुख कार्यशैली ही स्थायी बदलाव ला सकती है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकताओं से संगठनात्मक समन्वय, अनुशासन और सेवा-भाव के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कार्यशाला के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि पर्यावरण संरक्षण केवल योजनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि यह प्रयास जमीनी स्तर पर निरंतर और समन्वित प्रयासों से ही सफल हो सकता है। इसीक्रम में समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए स्थानीय सहभागिता के माध्यम से पर्यावरणीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। बैठक में संगठन की ह्लपंचतत्वह्व अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जल, वायु, ऊर्जा और वन्यजीव संरक्षण को प्रभावी कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। इसके साथ ही पदाधिकारियों को समन्वय, कार्य-विभाजन, जनसंपर्क और निगरानी तंत्र से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। इस अवसर पर धारा धर्म अभियान, प्रकृति जागरूकता साइकिल रैली (दिल्ली से वृंदावन), ग्राम वन योजना और टेरेस गार्डन योजना समेत अन्य पर्यावरणीय परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इन योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, ऊर्जा बचत और प्रकृति-अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने की प्राथमिक रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में वाइस चेयरमैन उद्वायन कुलश्रेष्ठ, सेंट्रल डायरेक्टर मीडिया बोर्ड अनुराग कुलश्रेष्ठ, केंद्रीय निदेशक सुधीर शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी (एडमिनिस्ट्रेशन) श्रीमती गीता वर्मा, केंद्रीय सदस्य अंकुर सिंह, निदेशक दिल्ली श्रीमती अनिता नागपाल, राज्य निदेशक उत्तर प्रदेश रवि शर्मा, राज्य सदस्य रामकुमार शर्मा और जिला सदस्य हर्ष ठाकुर समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। नेचर वेलफेयर काउंसिल ने सभी पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वह इस प्रकृति जागरूकता अभियान